शुगर इंडस्ट्री को मिला 6,600 करोड़ रुपये का राहत पैकेज

कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफेयर्स (सीसीईए) ने गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान करने के लिए शुगर इंडस्ट्री को इंटरेस्ट फ्री लोन देने का प्रपोजल गुरुवार को मंजूर कर लिया। एक अन्य अहम् फैसले में CCEA ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बफर स्टॉक को दोगुना करने का प्रस्ताव सेक्रेटरीज की कमेटी के पास भेज दिया। पेज 2

शुगर इंडस्ट्री को ₹6600 करोड़ का राहत पैकेज

किसानों का बकाया चुकाने के लिए शुगर इंडस्ट्री को मिलेगा इंटरेस्ट फ्री लोन

[ईटी ब्यूरो| नई दिल्ली]

कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफेयर्स (सीसीईए) ने गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान करने के लिए शुगर इंडस्ट्री को इंटरेस्ट फ्री लोन देने का प्रपोजल गुरुवार को मंजूर कर लिया। एक अन्य अहम फैसले में CCEA ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बफर स्टॉक को दोगुना करने का प्रस्ताव सेक्रेटरीज की कमेटी के पास भेज दिया। प्रस्ताव के मुताबिक, बफर स्टॉक को बढ़ाकर एक साल के लिए 5 करोड़ 30 लाख टन किया जाना है।

फूड मिनिस्टर के वी थॉमस ने बताया, 'शुगर इंडस्ट्री को लगभग 6,600 करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा।' इस रकम पर जो ब्याज लगेगा, उसे केंद्र सरकार शुगर डिवेलपमंट फंड के जरिए देगी। सरकार ने गन्ना किसानों के बढ़ते बकाया को देखते हुए इस राहत पैकेज का एलान किया है। सरकार की तरफ से तय गन्ने की ऊंची कीमत और चीनी की घटती कीमत के चलते चीनी मिलें गन्ना किसानों का बकाया चुकाने में नाकाम रही हैं।

एग्रीकल्चर मिनिस्टर शरद पवार की अगुवाई वाले इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपने प्रपोजल में यह सुझाव दिया था कि लोन सिर्फ गन्ना किसानों के पेमेंट के लिए दिया जाए। पवार ने इसी हफ्ते कहा था, 'यह प्रपोजल दो फेज में शुरू होगा- पहला इस हफ्ते और दूसरा अगले हफ्ते।' उन्होंने राहत पैकेज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था, लेकिन कहा कि लोन की रीस्ट्रक्चरिंग आरबीआई से क्लीयरेंस मिलने पर होगा। यह क्लीयरेंस इसी हफ्ते लिया जा सकता है।

CCEA ने भेजा प्रस्ताव

CCEA ने FCI के बफर स्टॉक को दोगुना करने का प्रस्ताव सेक्रेटरीज की कमेटी के पास भेज दिया। प्रस्ताव के मुताबिक, बफर स्टॉक को बढ़ाकर एक साल के लिए 5 करोड़ 30 लाख टन किया जाना है

शुगर इंडस्ट्री ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उसको उम्मीद है कि वह इस लोन से किसानों का पुराना समूचा बकाया चुका सकेगी। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (आईएसएमए) के डायरेक्टर जनरल अबिनाश वर्मा ने कहा, 'यह सरकार की तरफ से किसानों और इंडस्ट्री दोनों के लिए एक साथ उठाया गया शानदार कदम है। इस लोन से किसानों को समय पर उनका पेमेंट मिल जाएगा। इसके साथ ही उनका 3,000 करोड़ रुपये का पिछला बकाया भी क्लीयर हो जाएगा।'

उन्होंने कहा कि इस लोन से इंडस्ट्री को अगले पांच साल तक सालाना 500 करोड़ रुपये के ब्याज का बोझ घटाने में मदद मिलेगी।प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने गन्ना किसानों और शुगर इंडस्ट्री के मुद्दों पर गौर करने के लिए इस साल नवंबर में एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था। फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम, सिविल एविएशन मिनिस्टर अजित सिंह, पेट्रोलियम मिनिस्टर वीरप्पा मोयली और फूड मिनिस्टर के वी थॉमस इस पैनल का हिस्सा हैं। ग्रुप ने और जो अहम कदम उठाने का प्रपोजल दिया था उनमें 40 लाख टन रॉ शुगर प्रोड्यूस करने के लिए इनसेंटिव देना और बफर स्टॉक बनाना और पेट्रोल में एथनॉल की ब्लेंडिंग को मौजूदा 5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी करना शामिल है।

थॉमस ने बताया कि सीसीईए ने बफर स्टॉक के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव एक कमेटी के पास भेज दिया। उन्होंने बताया कि सेक्रेटरीज की कमेटी इस प्रस्ताव की समीक्षा करेगी।

Economic times

20/12/13